"G.S.अकादमी "

Committed To Your Success

Ai news

योजना / परियोजना

जनवरी - फरवरी

समाचार

प्रश्नोत्तर

www. gsacademycivil.com

Address: - Chandralok Tower, Kapoorthla, Lucknow.

9473893577

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का विश्लेषण -

फरवरी, 2020 में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संबंधी एक विश्लेषण किया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

(1) विश्लेषण के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा मरीजों को अन्य राज्यों में भेजकर पहले स्थान पर है।

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कुल 61,245 मरीजों का का विश्लेषण किया गया।

(3) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, लोकप्रिय आयुष्मान भारत योजना के रूप में भी जाना जाता है।

(4) इस योजना के तहत, हर गरीब परिवार को सालाना 5 लाख रुपये की स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 **(b) 2 और 3**

(c) 1 और 4 ***(d) 3 और 4***

संबंधित तथ्य -

- 25 फरवरी, 2020 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) द्वारा भारत सरकार की प्रमुख बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) पर एक विश्लेषण किया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विश्लेषण करने पर पाया गया कि कुल 81,254 मरीज पीएम-जेएवाई के तहत अन्य राज्यों में इलाज करवा रहे हैं।
- इसमें भी, मध्य प्रदेश राज्य ने कुल 11,765 मरीजों को गुजरात भेजकर पहला स्थान प्राप्त किया है।
- उत्तर प्रदेश ने उत्तराखंड में 4, 288 और महाराष्ट्र में 3572 मरीजों को भेजा है।
- बदले में बिहार ने 3258 मरीजों को उत्तर प्रदेश में भेजा है।
- अधिकांश मरीजों के आदान-प्रदान संबंधी मामले सामान्य सीमाओं वाले राज्यों के बीच होते हैं।
- उत्तर प्रदेश के ज्यादातर मरीज बिजनौर और सहारनपुर जिलों से यात्रा कर रहे हैं।
- 20 दिसंबर, 2019 तक, पीएम-जेएवाई ने कुल 70 लाख मरीजों के दावों को खत्म किया।
- ध्यातव्य है कि, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
- यह योजना भारत में वर्ष 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी।
- इस योजना का उद्देश्य, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (बीपीएल धारक) को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है।
- इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।

छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना –

5 मार्च, 2020 को किस केंद्रशासित प्रदेश में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया?

(a) लद्दाख ***(b) जम्मू-कश्मीर***
(c) लक्षद्वीप **(d) पुडेचेरी**

संबंधित तथ्य –

- **5 मार्च, 2020 को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल जी.सी. मुर्मू ने जम्मू में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया।**
- **योजनांतर्गत केंद्रशासित प्रदेश में जम्मू-कश्मीर छात्रों को शारीरिक और स्वस्थ्य बनाने हेतु विद्यालय स्तर पर उनकी नियमित जांच की जाएगी।**
- **इस योजना के अंतर्गत छात्रों को स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।**
- **इस योजना का उद्देश्य स्कूली छात्रों का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।**

==========******==========

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास –

29 फरवरी, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट जिले (उत्तर प्रदेश) में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया। इस एक्सप्रेस-वे के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?
(a) शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन भरतकूप स्थित गोंडा गांव में किया गया।
(b) इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 296 किमी. होगी।
(c) इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 15000 करोड़ रुपये होगी।
(d) इसका निर्माण कार्यदायी संस्था एल एंड टी द्वारा किया जा रहा है।

संबंधित तथ्य –

- 29 फरवरी, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट जिले (उत्तर प्रदेश) में बुंदे किया।
- शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन भरतकूप स्थित गोंडा गांव में किया गया।
- इस एक्सप्रेस-वे की लंबाई 296 किमी. होगी।
- इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 15000 करोड़ रुपये होगी।
- इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्यदायी संस्था यूपीडा द्वारा कराया जा रहा है।

- यह एक्सप्रेस-वे चित्रकूट के भरतकूप स्थित गोंडा गांव से प्रारंभ होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा में आगरा एक्सप्रेस-वे से जुड़ जायेगा।
- यह एक्सप्रेस वे 4 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 6 लेन किया जा सकेगा।
- इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे एवं यमुना एक्सप्रेस-वे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है।

==========******==========

10,000 किसान उत्पादक संघों की परियोजना –

29 फरवरी, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां 10,000 किसान उत्पादक संघों की परियोजना का शुभारंभ किया?

(a) लखनऊ **(b) प्रयागराज**
(c) चित्रकूट **(d) आगरा**

संबंधित तथ्य –

- 29 फरवरी, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्रकूट में 10,000 किसान उत्पादक संघो की परियोजना का शुभारंभ किया।
- इस परियोजना के माध्यम से किसान अपने उत्पादों की बिक्री उचित दामों पर कर सकेंगे।
- आकांक्षी जिलों में प्रत्येक विकास खंड में कम से कम एक एफ.पी.ओ. का गठन किए जाने को कहा।
- एफ.पी.ओ. को भारत सरकार द्वारा 15 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
- इन संगठनों से छोटे और भूमिहीन किसानों को एकजुट करने में मदद मिलेगी, जिससे वे प्रौद्योगिकी, उत्कृष्ट बीज उर्वरकों और कीटनाशकों सहित अपेक्षित वित्तीय साधनों की कमी जैसे मुद्दों से सामूहिक रूप से निपट सकें।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 9 राज्यों के 10 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करके सम्मानित किया।

==========******==========

मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्रों के समूह 'सोलर पार्क' की स्थापना –

27 फरवरी, 2020 को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा के अनुसार गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में राज्य में सौर ऊर्जा संयंत्रों के समूह 'सोलर पार्क' की स्थापना किस जिले में की जाएगी?

(a) इंदौर **(b) जबलपुर**
(c) सीहोर ***(d) शाजापुर***

संबंधित तथ्य –

- 27 फरवरी, 2020 को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने जानकारी प्रदान की कि गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के रूप में मध्य प्रदेश के महत्वाकांक्षी सौर ऊर्जा संयंत्रों के समूह 'सोलर पार्क' की स्थापना शाजापुर जिले में की जाएगी।
- इस जिले के शाजापुर एवं बड़ोदिया तहसील के 11 ग्रामों की 1272.822 हेक्टेयर भूमि पर इस सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी।
- इस सोलर पार्क की प्रतिदिन बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 450 मेगावॉट होगी।
- इस परियोजना की लागत राशि लगभग 1800 करोड़ रुपये है।
- इस सोलर पार्क को मार्च, 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इस सोलर पार्क से प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को बिजली प्रदान की जाएगी एवं वहां से बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी।

==========******==========

स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम –

27 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ कहां किया?

(a) रायपुर **(b) बिलासपुर**

(c) भुवनेश्वर **(d) नई दिल्ली**

संबंधित तथ्य –

- 27 फरवरी, 2020 को केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भुवनेश्वर, ओडिशा में 'स्थानीयस्व स्वशासन में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हेतु कार्यक्रम' का शुभारंभ किया।
- इसकी क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं में जनजातीय प्रतिनिधियों के निर्णय लेने की क्षमताओं में सुधार कर उन्हें सशक्त बनाना है।
- इस क्षमता निर्माण कार्यक्रम के मॉड्यूल को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संयोजन से विकसित किया गया है।
- इस अवसर पर उन्होंने 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स और जीआईएस आधारित पोर्टल लांच किया।
- 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स का उद्देश्य ग्रामीण भारत में कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों के लिए सुरक्षित एवं पर्यावरण जलापूर्ति में सुधार करना है।
- इस ऑनलाइन पोर्टल को स्प्रिंग्स पर आधारित डेटा तक पहुंच में सुधार करने हेतु लांच किया गया है।
- मौजूदा समय में स्प्रिंग एटलस पर 170 से अधिक स्प्रिंग्स का डेटा उपलब्ध है।

==========******==========

पीएमकेएसवाई के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी –

26 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरन कौर बादल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की यूनिट स्कीम के तहत कितने राज्यों की कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान गई?

(a) 10 **(b) 12**

(c) 15 ***(d) 17***

संबंधित तथ्य –

- 27 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरन कौर बादल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की यूनिट स्कीम के तहत 17 राज्यों की कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।
- इन परियोजनाओं में 406 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
- यह परियोजनाएं लगभग 15000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर केंद्रित है।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपये के तहत शुरू की गई है।
- इस योजना के तहत मेगा फूड पार्क की स्थापना, एकीकृत प्रशीतन गृहों की शृंखला, मूल्यवर्धन, अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण, क्लस्टरों के लिए अवसंरचना विकास तथा अन्य कई तरह की सुविधाएं शुरू की गई हैं।
- देश के खाद्य प्रसंस्करण बाजार के 14.6 प्रतिशत सीएजीआर की दर से वर्ष 2020 तक बढ़कर 543 अरब डॉलर का हो जाने की संभावना है।
- वर्ष 2016 में यह 322 अरब डॉलर था।

==========******==========

एमआईईडब्ल्यूएस वेब पोर्टल –

26 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बाजार बुद्धिमता और पूर्व चेतावनी प्रणाली (एमआईईडब्ल्यूएस) वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल फसलों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दृश्य फॉरमेट में प्रसार करेगा। कौन-सी फसल इसमें शामिल नहीं है?

(a) टमाटर **(b) प्याज**

(c) आलू ***(d) गोभी***

संबंधित तथ्य –

- 26 फरवरी, 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बाजार बुद्धिमता और पूर्व चेतावनी प्रणाली (एमआईईडब्ल्यूएस) वेब पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया।
- टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) के मूल्यों की वास्तविक निगरानी करने के साथ ही ऑपरेशन ग्रीन (ओग्री) योजना की शर्तों के तहत हस्तक्षेप करने संबंधी चेतावनी जारी करने के लिए एमआईईडब्ल्यूएस डैशबोर्ड और पोर्टल अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है।
- यह पोर्टल टीओपी (टमाटर, प्याज और आलू) फसलों से संबंधित प्रासंगिक जानकारी यथा मूल्य और आगमन क्षेत्र, उपज और उत्पादन, आयात और निर्यात, फसल कैलेंडर, फसल कृषि विज्ञान आदि के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी का दृश्य फॉरमेट में प्रसार करेगा।
- एमआईईडब्ल्यूएस प्रणाली किसानों को परामर्श देने के लिए तैयार की गई है, जिससे बहुतायत की स्थितियों में पूर्व चेतावनी मिलने के साथ-साथ चक्रीय उत्पादन से बचाव हो सके।
- यह पोर्टल योजना बनाने और कीमतें स्थिर करने हेतु समय पर हस्तक्षेप करने में मददगार होगा।
- यह पोर्टल एमओएफपीआई की पहल है, जो आईटी साधनों और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाती है।

==========******==========

20-20 सिस्टर सिटीज –

2 फरवरी, 2020 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने '20-20 सिस्टर सिटीज'की शुरुआत की। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

(1) इस परियोजना का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना है।

(2) मिशन के तहत, शहरों को एक समान क्षेत्र और संस्कृति वाले लोगों के साथ जोड़ा जाएगा।

(3) भोपाल अपने विचारों को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ साझा करेगा।

(4) मिशन को पूरा करने के लिए कुल 5,151परियोजनाओं की पहचान की गई हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

कूट :

(a) 1 और 2 **(b) 2 और 3**

(c) 1, 2 और 4 **(d) उपर्युक्त सभी**

संबंधित तथ्य –

- फरवरी, 2020 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 20 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों के साथ, 20 सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले शहरों की जोड़ी बनाई है, जो 'सिस्टर सिटीज' के रूप में काम करेंगे।
- ये 'सिस्टर सिटीज' एक ही मिशन (20 : 20 मॉडल) के तहत परियोजनाओं को लागू करने में एक-दूसरे की मदद करेंगे।
- 'सिस्टर सिटीज' को 100 दिनों में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए चुनौती दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में भारत सरकार ने देश के 100 शहरों को अच्छे शहरों के रूप में विकसित करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की थी।
- मिशन के अनुसार, शहरों को एक समान क्षेत्र और संस्कृति वाले शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। उदाहरण के लिए, एक पवित्र शहर वाराणसी को एक पवित्र शहर अमृतसर के साथ जोड़ा जाएगा।इसी प्रकार पहाड़ी महानगर को एक दूसरे राज्य के एक अलग पहाड़ी शहर, तटीय महानगर के तटीय महानगर, औद्योगिक महानगर को औद्योगिक महानगर से जोड़ा जाएगा।
- इसी प्रकार भोपाल अपने विचारों को मिजोरम की राजधानी आइजोल के साथ साझा करेगा।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में भारत में अहमदाबाद शहर सर्वश्रेष्ठ (Rank-1) स्मार्ट शहर है, जो परियोजनाओं को लागू करने में चंडीगढ़ की मदद करेगा।
- इसी तरह रांची और विशाखापत्तनम क्रमशः शिमला और दीव को अपना प्रदर्शन सुधारने में मदद करेंगे।
- इस परियोजना का उद्देश्य स्मार्ट समाधानों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना है।
- मिशन के तहत, कुल 5,151 परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिन्हें निष्पादित करने के लिए रु. 2,05,018 करोड़ की लागत आएगी।

==========******==========

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन का चौथा वार्षिक समारोह –

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन की शुरुआत कब की थी?

(a) 21 अक्टूबर, 2015 ***(b) 21 फरवरी, 2016***

(c) 22 मार्च, 2016 **(d) 24 अक्टूबर, 2017**

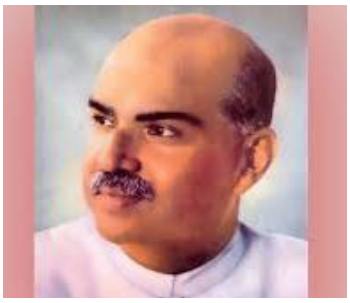

संबंधित तथ्य –

- 24 फरवरी, 2020 को केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन के चौथे वार्षिक समारोह का उद्घाटन किया।
- इस चौथे वार्षिक समारोह का शीर्षक 'आत्मा गांव की सुविधा शहर की' है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी, 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण मिशन की शुरुआत की थी।
- 21 फरवरी को इस मिशन के 4 वर्ष पूरे हुए।
- इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देकर गांवों का समुचित आर्थिक विकास करना है।
- मंत्रालय द्वारा इस मिशन के तहत अब तक 300 ‡लस्टर आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 296 को मंजूरी प्रदत्त की जा चुकी है।
- यह मिशन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं का समन्वय है, जिससे योजनाबद्ध एवं संगठित तरीके से क्षेत्र का समग्र विकास होता है।

==========******==========

जयललिता की जयंती (बालिका संरक्षण दिवस के रूप में) –

19 फरवरी, 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 'राज्य बालिका संरक्षण दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की। इस अवसर पर सरकार द्वारा बेसहारा लड़कियों के लिए कितनी योजनाओं की घोषणा की गई?

(a) 2 **(b) 3**

(c) 4 ***(d) 5***

संबंधित तथ्य –

- 19 फरवरी, 2020 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानी स्वामी ने विधानसभा में दिवगंत पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जयंती (24 फरवरी) को 'राज्य बालिका संरक्षण दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की।
- जयललिता ने बच्चों विशेषकर लड़कियों के कल्याण के लिए जिस लगन के साथ काम किया, उस महान सेवा की याद की रूप में राज्य सरकार ने उनकी जयंती को इस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है।

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेसहारा लड़कियों के कल्याण के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की।
- राज्य सरकार 21 वर्ष पूरे होने तक सरकारी घरों (अनाथालय) में रहने वाली प्रत्येक बेसहरा बालिका के नाम 2 लाख रुपये जमा करेगी।
- 18 वर्ष पूरे होने पर सरकारी घर छोड़ने पर राज्य सरकार बेसहारा लड़कियों को 50 वर्ष पूरे होने तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- इस वित्तीय सहायता से उन्हें उच्च शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण, रोजगार और स्व-रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने सरकारी घरों से बेसहारा लड़कियों को गोद लेने वाले माता-पिता के लिए पालन पोषण की मासिक सहायता राशि 2000 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किए जाने की भी घोषणा की।
- यह सहायता राशि 5 वर्ष तक प्रदान की जाएगी।
- इसके अलावा उन्होंने समाज कल्याण, सामाजिक न्याय, आईसीडीएस विभागों, सी और डी श्रेणियों में बेसहारा बालिकाओं को रोजगार देने की घोषणा की।
- मध्याह्न, भोजन केंद्रों और आंगनबाड़ी नौकरियों में भी उन्हें सरकार प्राथमिकता प्रदान करेगी।
- उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगाने हेतु पालना योजना शुरू की थी।

==========******==========

बेजोस अर्थ फंड –

17 फरवरी, 2020 को अमेजन के सीईओ और संस्थापक जेफ बेजोस ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने हेतु एक नया अर्थ फंड (बेजोस अर्थ फंड) शुरू करने की घोषणा की। इस फंड को शुरू करने के लिए वह कितनी राशि दान करेंगे?

(a) 5 बिलियन डॉलर
(b) 10 बिलियन डॉलर
(c) 12 बिलियन डॉलर
(d) 15 बिलियन डॉलर

संबंधित तथ्य –

- 17 फरवरी, 2020 को अमेजन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस ने एक नया अर्थ फंड शुरू करने की घोषणा की।

- इस फंड का नाम बेजोस अर्थ फंड होगा।
- इस फंड का उपयोग जलवायु परिवर्तन के मुकाबले के लिए किया जाएगा।
- वह इस फंड को शुरू करने के लिए 10 बिलियन डॉलर की राशि दान करेंगे।
- इस फंड से जलवायु वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों को राशि मुहैया कराई जाएगी।

==========******==========

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण - द्वितीय –

19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?

(a) दूसरे चरण की अवधि वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक होगी।

(b) दूसरे चरण में सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (ओडीएफ प्लस) पर फोकस किया जाएगा।

(c) दूसरे चरण हेतु कुल अनुमानित बजट 52,497 करोड़ रुपये रखा गया है।

(d) ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता को 2 लाख से 5 लाख रुपये कर दिया गया है।

संबंधित तथ्य –

- 19 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की।
- दूसरे चरण की अवधि वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक होगी।
- इस चरण में खुले में शौच से मुक्ति के बाद सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (ओडीएफ प्लस) पर फोकस किया जाएगा।
- जिसमें खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल होगा।
- दूसरे चरण के लिए कुल अनुमानित बजट वर्ष 2020-21 से 2024-25 की अवधि हेतु 52,497 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी।
- इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के क्रियान्वयन हेतु 30,375 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है।
- ओडीएफ प्लस कार्यक्रम मनरेगा के साथ शामिल होगा, विशेषकर धूसर जल प्रबंधन और नए जल जीवन मिशन कार्यक्रम को भी पूरा करेगा।

- इस कार्यक्रम अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण हेतु मौजूदा मानदंडों के अनुसार ही नए पात्र घरों को 12000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- ग्राम पंचायतों को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता को 2 लाख से 3 लाख रुपये कर दिया गया है।
- केंद्र एवं राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए फंड शेयरिंग का ढांचा पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बीच 90:10 अन्य राज्यों के बीच 60:40 और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के बीच 100:0 होगा।
- ओडीएफ प्लस के ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन घटक की निगरानी 4 प्रमुख क्षेत्रों-प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (पशु अपशिष्ट प्रबंधन भी शामिल), धूसर जल प्रबंधन और मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन के आउटपुट-इनपुट संकेतकों के आधार पर की जाएगी।
- देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज हेतु 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत की गई थी।

==========******==========

आस्कदिशा (ASKDISHA) चैटबॉट –

भारतीय रेलवे ने कब कृत्रिम बुद्धिमता (AI) पर आधारित ASKDISHA चैटबॉट की सेवाएं शुरू की थीं?

(a) अगस्त, 2017 **(b) अप्रैल, 2018**

(c) मई, 2018 ***(d) अक्टूबर, 2018***

संबंधित तथ्य –

- 21 फरवरी, 2020 को भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) ने जानकारी प्रदान की कि उसने ऑनलाइन चैटबॉट ASKDISHA (Digital Interaction to Seek Help Anytime) का हिंदी भाषा में रेलवे ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए उन्नयन किया है।
- भारतीय रेलवे ने अक्टूबर, 2018 में कृत्रिम बुद्धिमता (Al) पर आधारित 'ASKDISHA' चैटबॉट की सेवाएं शुरू की थीं।
- यह चैटबॉट आईआरसीटीसी द्वारा प्रदत्त विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में इंटरनेट पर प्राप्त रेलयात्रियों की समस्याओं का समाधान करने हेतु विकसित किया गया है।
- प्रारंभ में इस चैटबॉट को अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था।

- ASKDISHA पर हिंदी भाषा में दैनिक आधार पर औसतन 3000 पूछताछ की जा रही है और इस संख्या में दिन-प्रतिदिन बढ़ोत्तरी हो रही है।
- आईआरसीटीसी की निकट भविष्य में कई अन्य अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अधिकाधिक भाषाओं में इसकी शुरूआत करने की योजना है।

==========******==========

कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो रेल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन –

13 फरवरी, 2020 को किसने कोलकता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो रेल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया?

(a) नरेंद्र मोदी **(b) ममता बनर्जी**

(c) राम नाथ कोविंद ***(d) पीयूष गोयल***

संबंधित तथ्य –

- 13 फरवरी, 2020 को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो रेल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन किया।
- इससे सॉल्ट लेक के सेक्टर 5 और सॉल्ट लेक स्टेडियम के बीच 5.8 किमी. दूरी की सेवाएं शुरू हुई।
- इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री ने घोषणा की कि शेष 10.6 किमी. की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का काम दिसंबर, 2021 तक पूरा होगा।
- ईस्ट वेस्ट मेट्रो के पहले चरण पर लगभग 2400 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च हुई।
- कार्य पूर्ण हो जाने पर इस मेट्रो के जरिए कोलकाता और हावड़ा आपस में जुड़ जाएंगे।
- गौरतलब है कि पानी के भीतर रेल लाइन वाली यह देश की पहली सेवा है, जिसमें हुगली नदी के नीचे एक सुरंग के जरिए रेलगाड़ियां चलेंगी।

==========******==========

पठन मिशन (Reading Mission) की शुरुवात –

हाल में निम्न में से किस राज्य द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने हेतु पठन मिशन की शुरुआत की गयी है?

(a) पंजाब **(b) राजस्थान**

(c) उत्तर प्रदेश ***(d) हरियाणा***

संबंधित तथ्य –

- 10 फरवरी, 2020 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल द्वारा बताया गया है कि छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पठन-मिशन की शुरुआत की गई है।
- यह मिशन केंद्र सरकार के रीडिंग मिशन-2022 के तर्ज पर शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य पुस्तकों की खोई महिमा को वापस लाना है।
- मिशन के तहत शैक्षिक संस्थानों में महीने में एक बार छात्रों द्वारा पुस्तक समीक्षा सत्र आयोजित किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा महीने के चौथे शनिवार को 45 मिनट का सामूहिक पठन कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।
- पुस्तक का पठन समतावाद, सहिष्णुता और न्याय के सामाजिक मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है।

==========******==========

युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना –

9 फरवरी, 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में 10वीं, 12वीं एवं स्नातक के छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हेतु इसी वर्ष इंटर्नशिप योजना शुरू करने की घोषणा की?

(a) मध्य प्रदेश ***(b) उत्तर प्रदेश***

(c) राजस्थान **(d) हरियाणा**

Government of Uttar Pradesh (UP)

संबंधित तथ्य –

- 9 फरवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 10वीं, 12वीं और स्नातक के छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु इसी वर्ष से इंटर्नशिप योजना शुरू करने की घोषणा की।
- इस योजनांतर्गत छात्रों को विभिन्न तकनीकी शैक्षिक संस्थानों तथा उद्योगों से जोड़ा जाएगा।
- 6 महीन या 1 वर्ष की इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक युवा को 2500 रुपये की राशि प्रतिमाह भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी।

- इस 2500 रुपये की राशि में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 1500:1000 रुपये होगा।
- इंटर्नशिप का कार्यक्रम पूरा होने के बाद राज्य सरकार इन छात्रों को नौकरी दिलाने का प्रयत्न करेगी, जिसके लिए सरकार द्वारा एक एचआर सेल का गठन किया जाएगा।

==========******==========

उड़ान के तहत उत्तराखंड में पहली हेलीकॉप्टर सेवा –

8 फरवरी, 2020 को क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत उत्तराखंड में पहली हेलीकॉप्टर सेवा का प्रचालन किस मार्ग पर शुरू किया गया है?

(a) सहस्त्रधारा से गौचर और चिन्यालीसौड़ तक

(b) सहस्त्रधारा से हरिद्वार तक

(c) जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून से नई टिहरी तक

(d) देहरादून से श्रीनगर तक

संबंधित तथ्य –

- 8 फरवरी, 2020 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत सरकार को क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत देहरादून स्थित सहस्त्रधारा हेलीपैड से गौचर और चिन्यालीसौड़ हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन किया।
- इस सेवा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खोसला ने हरी झंडी दिखाई।
- यह उड़ान के तहत उत्तराखंड में शुरू की गई पहली हेलीकॉप्टर सेवा है।
- उड़ान-2 बोली प्रक्रिया के तहत इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मार्ग हेरिटेज एविएशन प्रदान किया है।
- हेरिटेज एविएशन सहस्त्रधारा से गौचर और चिन्यालीसौड़ तक प्रतिदिन एविएशन प्रदान किया है।
- हेरिटेज एविएशन सहस्त्रधारा से गौचर और चिन्यालीसौड़ तक प्रतिदिन 2 बार हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रचालित करेगा।
- मौजूदा समय में उड़ान के तहत हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रचालन चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से धर्मशाला और शिमला से कुल्लू के बीच किया जा रहा है।
- वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ाने के 260 मार्गों पर प्रचालन कर रहा है।
- शीघ्र ही उड़ान के तहत पवन हंस लिमिटेड जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून से नई टिहरी, श्रीनगर (चमोली, उत्तराखंड) और गौचर में भी प्रचालन शुरू करेगी।

उझ बहु-उद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना –

जम्मू-कश्मीर में उझ बहु-उद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी?

(a) रावी **(b) सिंधु**

(c) चिनाब ***(d) उझ***

संबंधित तथ्य –

- 3 फरवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर में उझ बहु-उद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना के संबंध में एक बैठक हुई।
- इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति (राज्यमंत्री) रतन लाल कटारिया, ऊर्जा मंत्री, पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने भाग लिया।
- इस बैठक में इस परियोजना के कार्यान्वयन को तेजी से ट्रैक करने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।
- बैठक में सिधु-जल संधि के तहत भारत के अधिकार के पूर्ण उपयोग पर चर्चा की गई।यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में रावी नदी की सहायक नदी उझ पर निर्मित की जाएगी।
- इस परियोजना से भारत उझ नदी के 781 मिलियन क्यूबिक मीटर जल का भंडारण करेगा। जिसका उपयोग सिंचाई व बिजली उत्पादन में होगा।
- इस परियोजना के निर्मित होने के बाद भारत आवंटित पूर्वी नदियों के पानी का पूर्ण उपयोग कर सकेगा।
- इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में करने का निर्णय किया गया है।
- इस परियोजना की निर्माण लागत राशि लगभग 5850 करोड़ रुपये होगी।

==========******==========

वाईएसआर पेंशन कनुका योजना –

1 फरवरी, 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने घर-घर पेंशन वितरण योजना 'वाईएसआर पेंशन कनुका' की शुरुआत को। इस योजना के तहत दिव्यांगों को प्रतिमाह कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।

(a) 2000 रुपये **(b) 2500 रुपये**

(c) 3000 रुपये **(d) 5,000 रुपये**

संबंधित तथ्य –

- 1 फरवरी, 2020 को आंध्र प्रदेश सरकार ने घर-घर (Doorstep) पेंशन वितरण योजना 'वाईएसआर पेंशन कनुका' की शुरुआत की।
- इस योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों को घर पर जाकर विभिन्न कल्याणकारी पेंशन प्रदान की जा रही है।

- साथ ही वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों की उम्र 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है।
- पेंशनभोगियों की उम्र सीमा कम करने के बाद इस वर्ष लाभार्थियों की संख्या 54.64 लाख हो जाएगी।
- दिव्यांगों को प्रतिमाह 3000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
- अज्ञात प्राचीन किडनी रोग (CKDU) (Chronic Kidney disease of Unknown)/ डायलिसिस पेंशन के लिए प्रतिमाह 5000 रुपये से 10000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक जानकारी प्राप्त स्वयंसेवक घर के दरवाजे पर जाकर पेंशन वितरित करेंगे।
- इस कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार ने लगभग 15.67 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।
- उल्लेखनीय है कि वृद्धों को घर-घर पेंशन देने की योजना नवरत्नालु योजना का नाम परिवर्तित कर सरकार ने 'वाईएसआर पेंशन कनुका' योजना कर दिया है।

==========******==========

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना –

21 जनवरी, 2020 को किस राज्य सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल के सतत विकास एवं संवर्धन हेतु मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए मंजूरी प्रदान की?

(a) उत्तर प्रदेश **(b) मध्य प्रदेश**

(c) छत्तीसगढ़ **(d) हरियाणा**

संबंधित तथ्य –

- 21 जनवरी, 2020 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई।
- प्रश्नगत प्रयोजना के संबंध में अग्रेतर आवश्यक निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
- इस योजनांतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पर्यटन स्थल का सतत विकास एवं संवर्धन किया जाएगा।
- पर्यटन केंद्र का चयन संबंधित विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार होगा।
- चयनित स्थल का विकास पर्यटन विभाग, विधायक निधि एवं सी.एस.आर. निधि से प्राप्त धनराशि से किया जाएगा।
- योजनांतर्गत रख-रखाव हेतु स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतों अथवा प्रबंध समिति गठित की जाएगी।
- योजनांतर्गत कार्य संबंधित विभागों के सहयोग से यथा आवश्यकतानुसार किए जाएंगे।

शिव भोजन योजना –

26 जनवरी, 2020 को किस राज्य में गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन योजना शुरू की गई है?

(a) उत्तराखंड ***(b) महाराष्ट्र***

(c) हिमाचल प्रदेश **(d) झारखंड**

संबंधित तथ्य –

- 26 जनवरी, 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित शिव भोजन योजना (Shiv Bhojan Scheme) की शुरुआत की।
- इस योजना का उद्देश्य गरीबों को मात्र 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना है।
- पायलट आधार पर शुरू की गई इस योजना के तहत थाली या लंच प्लेट सभी जिलों में निर्धारित समय के दौरान निर्दिष्ट केंद्रों एवं कैंटीनों में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- मुंबई में जिले के प्रभारी मंत्री असलम शेख ने नगर निकाय के नैयर अस्पताल की कैंटीन में इस योजना की शुरुआत की।
- इस पायलट योजना के तहत प्रत्येक जिला मुख्यालय पर शिव भोजन कैंटीन शुरू किया जाएगा।

==========******==========

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना –

26 जनवरी, 2020 को किस राज्य में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई है?

(a) मध्य प्रदेश **(b) छत्तीसगढ़**

(c) हरियाणा **(d) झारखंड**

संबंधित तथ्य –

- 26 जनवरी, 2020 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ किया और ग्रामीणों को परिवार पहचान- पत्र वितरित किए।
- इस योजनान्तर्गत आगामी 31 मार्च तक 20 लाख परिवारों को लाभ प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीणों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के तहत ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को योजना का लाभ प्रदान किया जाता है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम और 5 एकड़ से कम जमीन हो।

- इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना की राशि में से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मानधन की किश्तों को भरकर शेष राशि पात्र व्यक्ति के खाते में भेजी जाएगी।

==========******==========

विश्वास परियोजना और आश्वत परियोजना –

11 जनवरी, 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पुलिस द्वारा शुरू की गई विश्वास और आश्वत सहित भारतीय रेलवे की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया?

(a) हरियाणा ***(b) गुजरात***

(c) कर्नाटक **(d) महाराष्ट्र**

संबंधित तथ्य –

- 11 जनवरी, 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया।
- गुजरात दौरे पर गृह मंत्री ने गुजरात पुलिस की विश्वास और आश्वस्त सहित भारतीय रेलवे की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।
- विश्वास परियोजना के तहत राज्यभर में लगभग 34 जिलों और 7 पर्यटक स्थलों पर 7000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- आश्वस्त परियोजना के तहत साइबर अपराधों के पीड़ितों के लिए समर्पित देश की पहली हेल्पलाइन शुरू की गई है।

==========******==========

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क क्लस्टर –

रीवा संयंत्र के बाद मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है?

(a) शाजापुर ***(b) अगर-मालवा***

(c) नीमच **(d) शहडोल**

संबंधित तथ्य –

- 20 जनवरी, 2020 को मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने जानकारी प्रदान की कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना शाजापुर, अगर-मालवा और नीमच जिला क्लस्टर में की जा रही है।

- इन तीनों जिलों में सोलर पार्क की स्थापना की लागत राशि लगभग 6000 करोड़ रुपये होगी।
- इस सोलर पार्क से तीनों जिलों को कुल 1500 मेगावॉट बिजली मिलेगी।
- इसका निर्माण का पूरा करने का लक्ष्य मार्च, 2022 तक गया है।
- इन सोलर पार्कों से प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को बिजली प्रदान की जायेगी।
- अगर-मालवा जिले में 550 मेगावॉट क्षमता के सौर-ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है जो प्रदेश में रीवा संयंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा।
- नीमच जिले में 500 मेगावॉट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा रही है।
- शाजापुर जिले में 450 मेगावॉट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

==========******==========

100 रेल मार्गों पर प्राइवेट ट्रेनों का संचालन –

100 रेल मार्गों पर 150 ट्रेनों के संचालन हेतु किसने भारतीय रेलवे के साथ परिचर्चा पत्र तैयार किया है?

(a) कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स **(b) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

(c) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. ***(d) इनमें से कोई नहीं***

संबंधित तथ्य –

- जनवरी, 2020 में नीति आयोग ने भारतीय रेलवे के साथ एक परिचर्चा पत्र (प्राइवेट पार्टिसिपेशनः पैसेंजनर ट्रेस) तैयार किया।
- यह परिचर्चा पत्र निजी ऑपरेटरों को 100 रेलमार्गों पर 150 ट्रेन चलाने देने की अनुमति से संबंधित है।
- परियोजना में 22,500 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।
- इन मार्गों में मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली, नई दिल्ली-पटना, इलाहाबाद-पुणे और दादर-वडोदरा शामिल हैं।
- इनके अलावा हावड़ा-चेन्नई, हावड़ा-पटना, इंदौर-ओखला, लखनऊ-जम्मू तवी, चेन्नई-ओखला, आनंद विहार-भागलपुर, सिकंदराबाद-गुवाहाटी और हावड़ा-आनंद बिहार जैसे मार्ग भी शामिल हैं। जिन्हें 10 से 12 समूहों (क्लस्टर) में बांटा गया है।
- दस्तावेज के अनुसार, निजी कंपनियों को अपनी गाड़ियों में बाजार के अनुसार किराया वसूल की छूट होगी तथा वे अपनी सुविधानुसार विभिन्न श्रेणियों की बोगियां लगाने के साथ-साथ मार्ग पर उनके ठहरावा वाले स्टेशनों का भी चयन कर सकेंगी । ध्यातव्य है कि लखनऊ-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली 'तेजस एक्सप्रेस' IRCTC की ओर से परिचालित पहली भारतीय ट्रेन है।

==========******==========

आयुष्मान भारत योजना: NHA की दंडात्मक कार्यवाई –

आयुष्मान भारत योजना में धोखाधड़ी के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने दंडात्मक कार्यवाही के तौर पर साढ़े चार करोड़ रुपये के जुर्माने के अलावा कितने अस्पतालों को पैनल से बाहर कद दिया है?

(a) 125 अस्पतालों को **(b) 150 अस्पतालों को**

(c) 95 अस्पतालों को ***(d) इनमें से कोई नहीं***

संबंधित तथ्य –

- जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने 'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' में इम्पैनल्ड 171 अस्पतालों को पैनल से बाहर (Dempanlled) कर दिया तथा कदाचार में शामिल अस्पतालों पर 4.6 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।
- NAFU (नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट) ने अपनी पड़ताल में पाया कि इम्पैनल्ड अस्पतालों में कदाचार के मामले उपस्थित हैं।
- NHA के अनुसार, NAFU ने आंतरिक रूप से विकसित एल्गोरिदम (Algorithms) के आधार पर योजना के संदिग्ध ई-कार्डों का पता लगाया था और उचित कार्रवाई हेतु इस सूचना को राज्यों को भी साझा किया था।
- सरकार की इस महात्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना पांच लाख रुपये की कवरेज दी जाती है और वे सरकारी या निजी अस्पताल (इम्पैनल्ड) में कैशलेस इलाज करा सकते हैं।
- योजना के लाभार्थियों की संख्या वर्तमान में लगभग 10.74 करोड़ है जो गरीब, वंचित ग्रामीण परिवार और शहरी श्रमिकों की पेशेवर श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

==========******==========

यशस्विनी योजना –

11 जनवरी, 2020 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस राज्य में महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना का शुभारंभ किया?

(a) कर्नाटक **(b) राजस्थान**

(c) गोवा **(d) उत्तराखंड**

संबंधित तथ्य –

- 11 जनवरी, 2020 को केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने महिला उद्यमिता के लिए गोवा में यशस्विनी योजना का शुभारंभ किया।

- इस योजना की घोषणा पणजी के निकट तालेइगाओ में स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में हुआ।
- यशस्विनी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने स्वस्थ्य सखी परियोजना और स्तन कैंसर स्क्रीनिंग पहल का भी उद्घाटन किया।

==========******==========

ग्रीन क्रेडिट योजना –

जनवरी, 2020 में वन सलाहकार समिति द्वारा घोषित की गयी ग्रीन क्रेडिट योजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन- सा तथ्य सही है?

(i) वन विभाग को गैर सरकारी/निजी एजेंसियों को कारोबार की अनुमति देना।

(ii) 2020-30 तक 2.523 बिलियन टन कार्बन प्राप्त करना।

(iii) 30 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्रों का विकास करना।

(vi) ग्रीन इंडिया मिशन को पूरा करना।

कूट:

(a) 1, 2 **(b) 1, 2, 3**

(c) 2, 4 ***(d) उपर्युक्त सभी***

संबंधित तथ्य –

- जनवरी, 2020 में वन सलाहकार समिति (FAC) ने ग्रीन क्रेडिट योजना को मंजूरी प्रदान की।
- ग्रीन क्रेडिट योजना के तहत, वन विभाग को गैर-सरकारी निजी एजेंसियों को आउटसोर्स करने का अनुमति प्रदान की गई।
- यह योजना ग्रीन इंडिया मिशन के पूरक के तौर पर भी कार्य करेगी, जो जलवायु परिवर्तन से निबटने के लिए भारत की पहुंच में से एक हैं।
- ग्रीन इंडिया मिशन का लक्ष्य 2020-30 तक 2.523 बिलियन टन कार्बन कमी में उत्सर्जन करना है।
- इस योजना के तहत 30 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त वन क्षेत्र को विकसित करना है।
- ग्रीन क्रेडिट योजना उन संस्थाओं को अनुमति प्रदान करती है जो भूमि की पहचान करने और वृक्षारोपण करने के पात्र हैं।

==========******==========

उत्तर प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण –

6 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ब्लॉक स्तर पर सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया गया है?

(a) 25 **(b) 30**

(c) 35 **(d) 40**

संबंधित तथ्य –

- 6 जनवरी, 2020 को उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में ब्लॉक स्तर पर सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू हुआ।
- इस कार्यक्रम के तहत नियमित टीकाकरण दिवस, रविवार और छुट्टियों को छोड़कर टीकाकरण गतिविधि सात कार्य दिवसों में 4 राउंड में क्रियान्वित की जाएगी।
- पहला राउंड (दौर) विगत वर्ष दिसंबर, 2019 में पूरा हुआ था।
- अगला दौर फरवरी और मार्च महीने में संचालित किया जाएगा, जिसमें 73 जिलों के 425 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 5.5 लाख से अधिक बच्चों और लगभग 1.3 लाख गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु लगभग 66 हजार सत्र आयोजित किए जाएंगे।
- सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का प्रथम चरण 2 दिसंबर, 2019 को शुरू किया गया था और अंतिम चरण (चौथा चरण) 2 मार्च, 2020 तक संचालित होगा।
- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 90 प्रतिशत टीकाकरण करना है।

==========******==========

उजाला और स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम के 5 वर्ष –

5 जनवरी, 2020 को उजाला (सभी के लिए किफायती द्वारा उन्नत ज्योति) और एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) योजनाओं के 5 वर्ष पूरे हुए। इस संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?

(a) उजाला योजना के तहत पूरे देश में 36.13 करोड़ एलईडी बल्ब किफायती मूल्य में वितरित किए गए हैं।

(b) इससे प्रतिवर्ष 46.92 बिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत हुई है।

(c) एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) के अंतर्गत अभी तक देश में 1.03 करोड़ स्ट्रीट लाइटों को लगाया गया है।

(d) एसएलएनपी द्वारा मार्च, 2020 तक भारत में 1.85 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

संबंधित तथ्य –

- 5 जनवरी, 2020 को उजाला (सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति) और एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) योजनाओं के 5 वर्ष पूरे हुए।

- एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी) के अंतर्गत अभी तक देश में 1.03 करोड़ स्ट्रीट लाइटों को लगाया गया है, जिसके फलस्वरूप 6.97 बिलियन किलोवॉट प्रतिवर्ष ऊर्जा बचत हुई और इससे पीक डिमांड में 1161 मेगावॉट की कमी आई है।
- ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी प्रतिवर्ष 4.8 मिलियन टन कार्बनडाईऑक्साइड की कमी आई है।
- उजाला योजना अंतर्गत पूरे देश में 36.13 करोड़ एलईडी बल्ब किफायती दामों पर वितरित किए गए है।
- इससे प्रतिवर्ष 46.92 बिलियन किलोवॉट ऊर्जा की बचत हुई है और पीक डिमांड में 9394 मेगावॉट की कमी तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 38 बिलियन टन कार्बनडाइऑक्साइड की कमी आई है।
- भारत में एलईडी परितंत्र के निर्माण हेतु इन कार्यक्रमों को साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवॉर्ड 2017 सहित कई वैश्विक स्तर के पुरसकार प्राप्त हुए हैं।
- आईटी के नवाचार उपयोग हेतु एसएलएनपी को सीआईओ 100 पुरस्कार, 2019 प्राप्त हुआ है।
- एलईडी क्षेत्र में बदलाव आधारित योगदान हेतु उजाला और एसएलएनपी को ग्लोबल सॉलिड स्टेट लाइटिंग (SSL) पुरस्कार भी मिला है।
- उजाला योजना के तहत वितरित किए जाने वाले एलईडी बल्बों की कीमतों में कमी आई है।
- अनुमान है कि वर्ष 2020 तक भारतीय बाजार में एलईडी बल्ब की लाइटिंग मार्केट में हिस्सेदारी 60 प्रतिशत हो जाएगी।
- वर्ष 2018 में सरकार द्वारा शुरू की गए ग्राम स्वराज अभियान (जीएसए) के तहत 21058 गांवों को उजाला योजना के अंतर्गत किफायती दर पर एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं।
- विगत 5 वर्षों के दौरान 3,00,000 किमी. सड़कों पर एलईडी बल्ब लगाए गए हैं।
- एसएलएनपी द्वारा मार्च, 2020 तक भारत में 1.34 करोड़ पारंपरिक स्ट्रीटट लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- 5 जनवरी, 2015 को शुरू किया गया उजाला विश्व की सबसे बड़ी घरेलू लाइटिंग परियोजना और एलएलएनपी विश्व का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापन कार्यक्रम है।
- यह दोनों योजनाएं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (EESL) द्वारा लागू की गई हैं।

==========******==========

मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना –

4 जनवरी, 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय किया गया। इस योजना के संबंध में विकल्प में कौन-सा तथ्य सही नहीं है?

(a) इस योजनांतर्गत लगभग 12.55 लाख कर्मचारी अधिकारी लाभान्वित होंगे।

(b) सामान्य उपचारों के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

(c) गंभीर उपचारों के लिए 10 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।

(d) यह योजना 1 मार्च, 2020 से प्रभावी होगी।

संबंधित तथ्य –

- 4 जनवरी, 2020 को मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय किया गया।
- इस योजनांतर्गत लगभग 12.55 लाख कर्मचारी/अधिकारी लाभान्वित होंगे।
- इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नियमित शासकीय कर्मचारी, सभी संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन प्राप्तकर्ता पूर्णकालिक कर्मचारी और राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्राप्त होगा।
- इसके अलावा यह योजना निगम/मंडलों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों हेतु वैकल्पिक होगी।
- इस योजनांतर्गत बाह्य रोगी (ओपीडी) के रूप में प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये तक का निःशुल्क उपचार अथवा निःशुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा।
- योजनांतर्गत सामान्य उपचारों हेतु प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये और गंभीर उपचारों के लिए 10 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी।
- 10 लाख से अधिक के उपचार हेतु राज्य मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की जा सकेगी।
- यह योजना 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगी।

==========******==========

वाटर 4 चेंज -

24 नवंबर, 2019 को निम्नलिखित में से किस संस्थान ने 'वाटर 4 चेंज' परियोजना लांच की?

(a) जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन केंद्र
(b) केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय
(c) नीति आयोग
(d) भारतीय जल प्रबंधन संस्थान

दिल्ली साइकिल वॉक –

6 जनवरी, 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित तुगलकाबाद में दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी। द साइकिल वॉक ट्रैक की लंबाई कितनी होगी?

(a) 100 किमी. **(b) 150 किमी.**

(c) 200 किमी. **(d) 250 किमी.**

संबंधित तथ्य –

- 6 जनवरी, 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित तुगलकाबाद में 'दिल्ली साइकिल वॉक' परियोजना की आधारशिला रखी।
- इसका निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा किया जाएगा।
- इसकी अनुमानित निर्माण लागत राशि 550 करोड़ रुपये होगी।
- यह ट्रैक सिर्फ साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए निर्मित किया जा रहा है।
- दिल्ली साइकिल वॉक ट्रैक 200 किमी. लंबा होगा।
- इससे दिल्ली के वायु प्रदूषण में 20 प्रतिशत तक कमी आएगी।

Address: Chandralok Tower, Kapoorthla, Lucknow, Uttar Pradesh (9473893577)